



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(प्रसाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 25 अप्रैल, 2005/5 बैशाख, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

आदेश

शिमला-171009, 1 अप्रैल, 2005

संख्या पी०सी०एच०-एचए(5) 177/2002-7036-42.—यह कि उपायुक्त, कुल्लू, जिला कुल्लू द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार, प्रधान, ग्राम पंचायत जल्लूयां द्वारा स्थानीय जनता, ग्राम पंचायत जल्लूयां की शिकायत पत्र पर जांच के दौरान पंचायत समिति सदस्य श्री सेना पाल शर्मा, ग्राम पंचायत, जल्लूयां से माफीपट तथा दुर्व्यवहार करने के आरोप में उनके कार्यालय पत्र संख्या पी०सी०एच० (कु०) ग्राम पंचायत, कोट-2004-13/1-15, दिनांक 19-7-2004 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था ;

अतः यह कि मामले में वास्तविकता जानने हेतु हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत उपायुक्त, कुल्लू द्वारा उनके कार्यालय के पत्र संख्या पी०सी०एच०-(कु०) ग्रा० पं०

नोट 2004-1316-23, दिनांक 19-7-2004 द्वारा नियमित जांच श्री बी० सी० भण्डारी, परियोजना अधिकारी, ग्रामीण विकास अभिकरण, कुल्लू को सौंपी गई ;

अतः यह कि जांच अधिकारी द्वारा की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट उपायुक्त, कुल्लू से उनके कार्यालय के पत्र संख्या 2160 दिनांक 22-11-2004 के अन्तर्गत निदेशालय में प्राप्त हुई तथा जांच रिपोर्ट में दर्शाए गए तथ्यों का बारीकी से अध्ययन करने उपरान्त श्री देवेन्द्र कुमार, प्रधान, ग्राम पंचायत जल्लूग्रां द्वारा गठित समिति सदस्य श्री सेनापाल शर्मा, ग्राम पंचायत जल्लूग्रां से मारपीट, दुर्व्यवहार करने तथा जांच कार्य में व्यवधान डालने के दोषी पाए गए जिसके फलस्वरूप उन्हें सरकार द्वारा दिनांक 23-12-2004 को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत प्रधान पद से निष्कासित करने से पूर्व विकासार्थ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न उन्हें प्रधान पद से निष्कासित किया जाए तथा 15 दिनों के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया गया ;

अतः यह कि श्री देवेन्द्र कुमार प्रधान, (नि०), ग्राम पंचायत जल्लूग्रां द्वारा प्रस्तुत उक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर से सरकार सन्तुष्ट नहीं हुई, क्योंकि उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है । जिसके फलस्वरूप श्री देवेन्द्र कुमार, प्रधान, ग्राम पंचायत जल्लूग्रां, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1)(ख) के अन्तर्गत दुराचार के दोषी पाये जाने के कारण उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 146(1) के अन्तर्गत प्रधान पद से हटाया जाना आवश्यक है ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जोकि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए श्री देवेन्द्र कुमार, प्रधान, ग्राम पंचायत जल्लूग्रां, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू को उक्त कृत्य के लिए प्रधान पद से तुरन्त निष्कासित किया जाता है तथा छः वर्ष की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 146(2) के अन्तर्गत पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन के लिए निरहित किया जाता है ।

शिमला-171009, 4 अप्रैल, 2005

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5) 102/2004-7142-7148.—यह कि श्रीमती सुरेश कुमारी, प्रधान, ग्राम पंचायत हीरापुर के विरुद्ध श्री सुरेश पाल, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत हीरापुर एवं अन्य वाई पक्षों से प्राप्त गिकाया पत्र पर प्रारम्भिक छानबीन उप निदेशक एवं उप सचिव (पंचायत), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई । जिनके फलस्वरूप श्रीमती सुरेश कुमारी, प्रधान, ग्राम पंचायत हीरापुर, राजीव आवास योजना के अन्तर्गत मकान निर्माण हेतु मु० 18,000/- ₹० की राशि गलत प्रमाण-पत्र देकर श्रीमती मान देई पत्नी श्री अनन्त राम को प्रदान करने की सिफारिश कर लाभार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने की दोषी पाई गई हैं ;

अतः यह कि मामले की वास्तविकता जानने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत उपायुक्त, बिलासपुर द्वारा उनके कार्यालय के पत्र संख्या बी० एल० पी० पंच-5321-25, दिनांक 26-10-2004 द्वारा नियमित जांच जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सौंपी गई ;

अतः यह कि जांच अधिकारी द्वारा की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट उपायुक्त, बिलासपुर से उनके कार्यालय पत्र संख्या बी० एल० पी० पंच-5933, दिनांक 3-1-2005 के अन्तर्गत निदेशालय में प्राप्त हुई तथा जांच रिपोर्ट में दर्शाये गये तथ्यों का बारीकी से अध्ययन करने उपरान्त सरकार के ध्यान में दिया कि श्रीमती सुरेश कुमारी द्वारा वहेसियत प्रधान, ग्राम पंचायत हीरापुर, विकास खण्ड झण्डता, जिला बिलासपुर, श्रीमती मान देई पत्नी श्री अनन्त राम को राजीव आवास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि मु० 22,000/- ₹० में से मु० 6000/- ₹० प्रथम किश्त तथा मु० 12,000/- ₹० द्वितीय किश्त मौके पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किये बगैर जारी कर लाभार्थी को अनुचित लाभ पहुंचा कर कुल मु० 18,000/- ₹० की

राशि का दुरुपयोग किया है। लाभार्थी द्वारा भी उक्त राशि का प्रयोग अपने पुराने मकान की मरम्मत पर व्यय किया है केवल शौचालय ही नया बनाया है। यदि यह मामला प्रकाश में नहीं आता तो प्रधान द्वारा गलत प्रमाण-पत्र जारी करने की बजह से मु० 18,000/- रु० की सरकारी राशि का दुरुपयोग हो जाता। यद्यपि उपरोक्त राशि लाभार्थी द्वारा दिनांक 19-10-2004, रसीद संख्या-1927533 अनुसार खण्ड विकास अधिकारी, झण्डूता के कार्यालय में जमा कर दी गई है।

अतः यह कि जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने उपरान्त श्रीमती सुरेश कुमारी, प्रधान, ग्राम पंचायत हीरापुर को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1)(बी) के अन्तर्गत उपरोक्त दर्शाये गये कृत्यों के लिये दुराचार के दोषी पाये जाने के फलस्वरूप दिनांक 16-2-2005 को निष्कासनार्थ कारण बनाओ नोटिस जारी किया गया।

अतः यह कि श्रीमती सुरेश कुमारी, प्रधान, ग्राम पंचायत हीरापुर ने उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिनांक 9-3-2005 को प्रस्तुत कर सचित किया है कि उन द्वारा श्रीमती मान देई लाभार्थी को राजीव आवास योजना के अन्तर्गत मकान निर्माण हेतु स्वीकृत राशि को जारी करने हेतु सिफारिश मौका निरीक्षण किये बगैर बिपरीत पारिवारिक परिस्थितियों तथा पंचायत सचिव द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर गया किया था।

उपरोक्त के दृष्टिगत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145(6) के अन्तर्गत श्रीमती सुरेश कुमारी, प्रधान, ग्राम पंचायत हीरापुर को भविष्य में सचेत रहने बारे चेतावनी दी जाती है।

शिमला-171009, 8 अप्रैल, 2005

संख्या पी० सी० एच०-एच०ए० (5) 104/99-7288-94.—यह कि उपायुक्त, सिरमौर द्वारा श्री चमेल सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत बान्दली, विकास खण्ड शिलाई को विकास कार्यों हेतु स्वीकृत सरकारी धनराशि के दुरुपयोग एवं छत्रहरण में संलिप्त होने के आरोप में उनके कार्यालय आदेश संख्या पी० सी० एच०-एच० (5) 85/99-4-1240-50, दिनांक 19-6-2002 द्वारा प्रधान, ग्राम पंचायत बान्दली के पद से निलम्बित किया गया था;

यह कि मामले की वास्तविकता जानने हेतु नियमित जांच हिमाचल प्रदेश, पंचायतती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत उप-मण्डल अधिकारी, पांवटा, जिला सिरमौर को विभाग के आदेश संख्या पी० सी० एच०-एच०ए० (5) 104/99-31303-309, दिनांक 29-11-2002 को सौंपी गई थी;

अतः यह कि जांच अधिकारी से प्राप्त जांच रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन करने उपरान्त निम्न तथ्य समक्ष आये:—

क्र० सं०	निर्माण कार्यों का नाम अथवा प्रयोजन	मद	स्वीकृत राशि	खर्च दर्शाई गई या प्रधान को अग्रिम राशि	मूल्यांकन राशि	बकाया अधिक निकाली गई राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	निर्माण पक्की गली हुरिजन बस्ती डाका।	जे० जी० एस० वाई०।	28,500/-	28,418/-	मौके पर कार्य नहीं हुआ है।	28,418/-
2.	निर्माण पक्का रास्ता प्रा० पा० से निचली बान्दली।	11वाँ वित्त आयोग।	16,000/-	16,000/-	—यथा—	16,000/-

1	2	3	4	5	6	7
3.	मुरम्मत सिचाई टैंक पण्डोग निर्माण।	जे 0 जी 0 एस 0 वाई 0।	7,000/-	7,000/-	2,452/-	4,548/-
4.	निर्माण सिचाई कुहल पंडोग नाला से बडियार।	-यथा-	20,000/-	20,000/-	10,913/-	9,087/-
5.	निर्माण साईड ड्रेन (गंदी नाली) ग्राम कुफर।	10वां वित्त आयोग	10,000/-	10,000/-	4,266/-	5,734/-
6.	निर्माण पशु खुरली ग्राम भगयारी।	11वां वित्त आयोग	3,000/-	3,000/-	2,062/-	938/-
7.	निर्माण खज्वर रास्ता काण्डोधार से घघास।	10वां वित्त आयोग।	15,000/-	15,000/-	2,965/-	12,035/-
8.	निर्माण सांझा आंगन घघास।	जे 0 जी 0 एस 0 वाई 0।	12,000/-	12,000/-	2,743/-	9,257/-
योग			1,11,500/-	1,11,418/-	25,401/-	86,017/-

अतः उपरोक्त कार्यों पर प्रधान द्वारा मु० 1,11,418/- रु० अग्रिम के रूप में प्राप्त किए तथा व्यय दर्शाए गए है जबकि निर्माण कार्यों का मूल्यांकन मु० 25,401/- रु० किया गया है। इस प्रकार श्री चमेल सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत, बान्दली द्वारा मु० 86,017/- रु० की सरकारी धनराशि का दुरुपयोग तथा गवन किया गया है।

अतः यह कि जांच रिपोर्ट पर विचार करने उपरान्त श्री चमेल सिंह, प्रधान (नि०), ग्राम पंचायत बान्दली द्वारा बर्ती गई वित्तीय अनियमितताओं तथा मु० 86,017/- रु० की राशि के दुरुपयोग किए जाने के फलस्वरूप इस कार्यलय के समसंख्यक आदेश दिनांक 15-12-2004 के अन्तर्गत उन्हें निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न उन्हें प्रधान पद से निष्कासित किया जाए तथा 15 दिनों के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया गया ;

अतः यह कि श्री चमेल सिंह, प्रधान (नि०), ग्राम पंचायत, बान्दली द्वारा प्रस्तुत उक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर से सरकार सन्तुष्ट नहीं हुई, क्योंकि उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है। जिसके फलस्वरूप श्री चमेल सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत, बान्दली, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) के अन्तर्गत विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आपत्तिजनक कार्यकलाप के फलस्वरूप के दोषी पाये जाने के कारण उन्हें प्रधान पद से हटाया जाना आवश्यक है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अधीन जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए श्री चमेल सिंह, प्रधान (नि०), ग्राम पंचायत बान्दली, विकास खण्ड शिलाई, जिला सिरमौर को उक्त कृत्य के लिए प्रधान पद से तुरन्त निष्कासित किया जाता है तथा छः वर्ष की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 146 (2) के अन्तर्गत पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन के लिए निरहित किया जाता है।

आदेश द्वारा

हस्ताक्षरित/-
सचिव।